

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 109/2021

तारीख रजू 09.03.2021

हरिबल्लभ पुत्र शंकर जाति जाट निवासी सावंलपुर।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार

----- रेस्पोंड

निर्णय

दिनांक 10/8/21

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 18/2021 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सावंलपुर के आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 1.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसों की फसल काशत करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंड की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 1 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर अपीलान्त को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जबकि अपीलान्त की खातेदारी कब्जे काशत की आराजीयात पास में स्थित है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया व एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ

1c  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर




न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेशकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्त के को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। तथा चरागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि है यदि उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो मवेशियों के विचरण करने एवं चारा चरने पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्त को स्वयं को नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्त अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान शामिल मिसल है तथा अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण मूक पशुओ विचरण एवं चारा चरने पर कुप्रभाव डाला गया है। मैं वकील पेशकार की बहस से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.21 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर